दैनिक आचरण, सागर

- 3 JAN 2015

नीति आयोग का गठन एक क्रांतिकारी पहल

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर बनाए गए नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की तारीफ करते हुए आज कहा कि इससे भारत केरूपांतरण की विकास प्रक्रिया तेज होगी। चौहान ने ट्वीट के जरिए कहा कि यह आयोग भारत कीविकास संबंधी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने में काफी मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि नई सोच वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गठित किए गए इस आयोग की विशेष बात यह है कि मुख्यमंत्रियों के सुझाव लेकर और उनसे विचार विमर्श करने के बाद इसका गठन किया गया है। इसकी 'गवनिर्ंग काउंसिल' में मुख्यमंत्रियों के अलावा केन्द्र शासित राज्यों के उप राज्यपालों को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था से राज्यों के विकास को नईदिशा मिलेगी। श्री चौहान ने कहा कि इससे राज्यों के बीच विवादास्पद मुद्दों के समाधान के लिए क्षेत्रीय परिषदों का भी गठन किया गया है। ऐसा करने से विकास में बाधक मुद्दों का तेजी से समाधान हो सकेगा। इससे विकास में अधिक सक्रियता और तत्परता से योगदान किया जा सकेगा।

चौहान ने कहा कि भारत ने नए वर्ष की सुबह सहकार औरलोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित विकास के नए युग में आंखें खोली हैं। यह युग प्रवर्तक परिवर्तन भारत योजना आयोग के स्थान पर बनाये गये 'नीति' आयोग केरूप में आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1952 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के चहुंमुंखी विकास के लिए जिस योजना आयोग का गठन किया था वह उस दौर की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के संदर्भ में ठीक था। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश का जो विकास हुआ उसमेंआयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विकास के नियोजन और योजनाओं के निर्माण तथा क्रियान्वयन में योजना आयोग ने काफी हद तक अच्छा काम किया। लेकिन बीते कुछ दशक में विशेष कर 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद योजना आयोग के वर्तमान स्वरूप के अस्तित्व की प्रासांगिकता लगातार खत्म होती चली गई। चौहान ने कहा कि लोकतंत्र में विभिन्न प्रदेश में अलग-अलग राजनैतिक दलों की सरकारें होती हैं। जिससे यह बात लगातार महसूस की जा रही थी कि केन्द्र में सत्ताधारी दल के राजनैतिक हितों के संवर्धन में आयोग के राज्यों के साथ राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्रह और दुराग्रह सहायक होने लगे थे। धनराशि के आवंटन में इसी कारण राज्यों के साथ भेदभाव की बात तीव्रता से महसूस की जा रही थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना आयोग की कार्य-प्रणाली में लोकतांत्रिक भावना का अभाव हो गया था।

योजना निर्माण की प्रक्रिया मे राज्यों और उनके मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली चर्चा रस्म अदायगी बन गई थी। योजनाएँ केन्द्र से बनाकर राज्यों को भेजी जा रही थीं। इनमें राज्यों की भौगोलिक सामाजिक आर्थिक एतिहासिक और सांस्कृतिक विष्टिताओं का ध्यान नहीं रखा जाता था। चौहान ने कहा कि इसी कारण योजनाओं का वांछित लाभ आम लोगों को नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने लगातार यह बात अनेक मंचों से कही कि जिस तरह हर मर्ज की एक दवा नहीं हो सकती उसी तरह हर राज्य के लिए एक समान योजना नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के विषय में यह बात ज्यादा लागू होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में उन्होंने यह काम पहले ही कर लिया है। प्रदेश के गांवों के विकास के लिए मास्टर प्लान ग्रामीणों के सुझाव सहमति और भागीदारी से बनाए गए हैं। जिनके क्रियान्वयन की शुरुआत भी हो गई है। श्री चौहान ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि नया आयोग पूरे देश में इस प्रकिया को आगे बढाएगा। जिससे प्रत्येक गांव में मौजूद संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए इनका तेजी से विकास संभव हो सकेगा।